



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 वैशाख 1939 (श०)

(सं० पटना 355) पटना, मंगलवार, 2 मई 2017

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

9 मार्च 2017

सं० 22 नि० सि० (पट०)—03—14/2006/386—श्री मुन्द्रिका सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता (आई० डी०—3890) के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 का नियम—17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापक 830 दिनांक 12.08.06 द्वारा निम्न आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी:—

(1) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची की अधिसूचना सं० 3733 दिनांक 04.09.04 के निदेशानुसार बिहार कैडर आवंटन के पश्चात झारखण्ड सरकार स्थित अपने पूर्व पद का विधिवत प्रभार प्रतिवेदन नहीं सौंपा जाना।

(2) बिहार कैडर आवंटन के फलस्वरूप जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय में विलम्ब से बिना कोई पूर्व सूचना दिए दिनांक 24.05.05 को बिना पूर्व पद का प्रभार सौंप विभाग में योगदान देना।

(3) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय में योगदान देने के पश्चात विभागीय पत्रांक 2882 दिनांक 04.07.05 द्वारा योगदान को अस्वीकृत कर निदेश दिया गया कि पूर्व पद का प्रभार सौंप कर स्पष्ट करें कि विलम्ब से योगदान क्यों दिया गया, ताकि उनके योगदान को स्वीकृत कर पदस्थापन की कार्यवाई की जा सके। उन्होंने यह पत्र दिनांक 11.07.05 को स्वयं प्राप्त किया परन्तु उसका उत्तर आज तक विभाग को नहीं उपलब्ध कराया गया।

(4) उनसे स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक 4084 दिनांक 07.10.05 एवं स्मार पत्रांक 4518 दिनांक 30.11.05 द्वारा उनके बायोडाटा में अंकित स्थायी पता पर पत्र भेजा गया परन्तु पत्र विभाग को वापस चला आया।

(5) मुख्यमंत्री, बिहार, पटना को संबोधित उनका पत्र दिनांक 18.12.05 एवं 26.12.05 में उनके द्वारा उनके स्थानीय पता मकान नं०—101/सी०, आशियाना नगर, फेज—1, पटना—25 अंकित किया गया है। स्थानीय पता पर भी योगदान हेतु विभागीय पत्रांक 370 दिनांक 06.02.06 निबंधित डाक से भेजा गया परन्तु इस पत्र का भी उत्तर विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया।

(6) अंततः विभाग द्वारा दिनांक 15.04.06 को हिन्दुस्तान, हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति किया गया कि विभाग में योगदान देकर आयुक्त एवं सचिव के समक्ष एक सप्ताह के अन्दर उपस्थित हों परन्तु इस निदेश का भी अनुपालन नहीं किया गया।

(7) मुख्यमंत्री, बिहार को संबोधित उनका पत्र विभाग को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 का उल्लंघन किया है।

विभागीय कार्यवाही के संचालन में श्री सिंह को अपना बचाव बयान प्रस्तुत करने हेतु संचालन पदाधिकारी द्वारा कई अवसर प्रदान किया गया, किन्तु श्री सिंह विभागीय कार्यवाही के संचालन में उपस्थित होकर अपना बचाव

बयान प्रस्तुत नहीं किया, संचालन पदाधिकारी द्वारा इनके पते पर निबंधित डाक से भी बचाव बयान प्रस्तुत करने हेतु पत्र भेजा गया था इसके बावजूद श्री सिंह द्वारा अपना बचाव बयान प्रस्तुत नहीं किया गया, परिणामस्वरूप संचालन पदाधिकारी ने विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए साक्ष्य के आधार पर अपना अभिमत अंकित करते हुए श्री सिंह के विरुद्ध गठित सभी 7 (सात) आरोपों में से आरोप सं०-4 एवं 5 को छोड़कर शेष आरोपों को प्रमाणित होने का मतव्य दिया गया।

इसी बीच श्री सिंह दिनांक 31.07.12 को सेवानिवृत्त हो गए जिसके उपरान्त उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश सं० 146 दिनांक 15.12.14 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी०) में सम्परिवर्तित करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 216 दिनांक 22.01.15 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी परन्तु श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब नहीं दिया गया। तदोपरान्त इस संबंध में दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 25.08.15 को प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गयी। इसके बावजूद भी श्री सिंह ने द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किया। फलस्वरूप उनके पेंशन से 5 (पाँच) प्रतिशत कटौती का दण्ड प्रस्ताव दिया गया परन्तु उनका योगदान स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में प्रस्तावित दण्ड पर कोई निर्णय नहीं हो सका।

सम्पूर्ण तथ्यों को अंकित करते हुए संचिका परामर्श हेतु विधि विभाग, बिहार, पटना को भेजी गयी। जिसपर विद्वान महाधिवक्ता, बिहार ने परामर्श दिया कि “कैंडर विभाजन के पश्चात श्री सिंह स्वतः बिहार संवर्ग के अभियंता माने जाएंगे। इसलिए संबंधित अनुशासनिक प्राधिकार श्री सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अंतिम निर्णय ले सकता है”। श्री सिंह दिनांक 24.05.05 को इस विभाग में योगदान दिए उसके पश्चात वह कभी भी उपस्थित नहीं हुए एवं दिनांक 31.07.12 को सेवानिवृत्त हो गए। इस प्रकार श्री सिंह योगदान की तिथि 24.05.05 से सेवानिवृत्ति की तिथि 31.07.12 तक करीब 7 वर्षों तक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहे। इस संबंध में स्पष्टीकरण माँगे जाने एवं विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने के दौरान भी उपस्थित नहीं हुए बल्कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित पत्र में इनके द्वारा अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया।

विभागीय कार्यवाही के संचालन में संचालन पदाधिकारी ने श्री सिंह के विरुद्ध गठित सभी आरोपों को (आरोप सं० 4 एवं 5 को छोड़कर) प्रमाणित होने का मतव्य दिया है तथा इनके आचरण को बिहार सरकारी सेवक आचरण का नियम-3(i) (क) एवं नियम-10 के प्रतिकूल बताया गया है।

अतः विभागीय अभिलेखों के आधार पर समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री मुन्द्रिका सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता (आई० डी० सं० 3890) के विरुद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है:-

“पेंशन पर सदा के लिए रोक”।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री मुन्द्रिका सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता (आई० डी० सं० 3890) के विरुद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए उन्हें संसूचित किया जाता है:- “पेंशन पर सदा के लिए रोक”।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
जीउत सिंह,  
सरकार के उप-सचिव।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**

**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**

**बिहार गजट (असाधारण) 355-571+10-डी०टी०पी०।**

**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**